जनसत्ता

पाक को सबक

इस बात में अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकी संगठनों को पाल रहा है और उन्हें भरपूर मदद दे रहा है। आतंक फैलाने वाले देशों पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए उसे 'काली सूची' में डाल दिया है। यह कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए इस बात का सख्त संदेश है कि अगर उसने अभी भी आतंकवाद का कारोबार नहीं छोड़ा तो जल्द ही वह और मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि कुछ ही महीने पहले जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने कुछ आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का अभियान तो चलाया था, लेकिन वह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं था। एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत समूह की ऑस्ट्रेलिया में हुई लंबी बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। एफएटीएफ ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो चालीस पैमाने बनाए थे उनमें से बत्तीस पर पाकिस्तान जरा भी खरा नहीं उतरा। जाहिर है, उसने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जैसा कुछ किया ही नहीं।

पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद की फैक्टरी के रूप में कुख्यात है। उसका सबसे बड़ा मददगार और हमदर्द अमेरिका तक कह चुका है कि वह धरती पर आतंकवाद फैलाने वाला सबसे बड़ा देश है। अमेरिका को दहला देने वाला अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सुरक्षा में रह रहा था। आतंकी संगठनों को पनाह देने, उन्हें पालने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है! चाहे अफगानिस्तान हो या भारत, सब जगह उसने एक तरह से छाया युद्ध चला रखा है। भारत तो तीन दशक से सीमापार आतंकवाद झेल ही रहा है। संसद पर हमला, मुंबई हमला, पठानकोट और उड़ी हमले के तो भारत ने पुख्ता सबूत तक दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इन सबूतों को नहीं माना। हैरानी की बात तो यह है कि इन हमलों की जिम्मेदारी उसके यहां बैठे आतंकी संगठन लेते रहे हैं लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती रही है। एफएटीएफ पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तान को चेता रहा है लेकिन उसकी सारी कवायद बेअसर ही साबित हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे निगरानी सूची में डाला जाता है या काली सूची में। वह आज भी भारत के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है। पुलवामा का हमला तो ताजा मिसाल है। हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि पुलवामा जैसे हमले और हो सकते हैं। यह कौन नहीं जानता-समझता कि भारत में ऐसे आतंकी हमले कौन करवा रहा है!

एफएटीएफ का एशिया प्रशांत समूह आतंकी संगठनों को पैसा उपलब्ध कराने वाले, जनसंहार करने वाले हथियारों की खरीद के लिए होने वाले वित्तीय लेनदेन से रोकने वाली एक क्षेत्रीय संस्था है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही एफएटीएफ कार्रवाई करती है। यह समूह पाकिस्तान से आइएस, अलकायदा, जमात-उद-दावा, लश्करे तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहता रहा है। लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा है। निगरानी सूची में रहने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। आतंक पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आतंकी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो। इसके लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है। हालांकि अब तक का अनुभव बताता है कि उससे ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ ही है।

मौत के सीवर

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर हमारा देश चांद और मंगल पर या फिर अंतरिक्ष में शोध और अध्ययन के लिए उच्च क्षमता के प्रक्षेपण यानों को भेज कर नित नए वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है और दूसरी ओर सीवर की सफाई के जो मौजूदा इंतजाम हैं, उनमें इंसानों की जान चली जा रही है। जाहिर है, यह राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी का ही उदाहरण है कि जिन कामों में मशीनों की जरूरत सबसे ज्यादा है, वे आज भी साधारण लोगों के बूते चल रहे हैं और अक्सर उनके मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक सीवर लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। ऐसी तमाम घटनाओं की तरह एक बार फिर इसे भी आम दुर्घटना के रूप में ही देखा जाएगा और किसी रिवायत की तरह मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शायद फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगेगा। सवाल है कि घातक जोखिम के अलावा इस काम के संबंध में तमाम कानूनी व्यवस्था के बावजूद अगर जानलेवा सफाई में लोगों को झोंका जा रहा है और उनकी जान जा रही है तो क्या इसे परोक्ष रूप से हत्या की घटनाएं नहीं कहा जा सकता है!

हाल ही में आए एक अध्ययन के मुताबिक, केवल इस साल के शुरुआती छह महीनों में ही सीवर की सफाई करते हुए पचास से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले लगभग ढाई दशक के दौरान करीब सवा छह सौ लोग यही काम करते हुए मारे गए। आखिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और इससे संबंधित कानूनों के लागू होने के बावजूद यह काम सरेआम कैसे चलता रहा है? ऐसी घटनाओं में लगातार होने वाली मौतों के बावजूद सीवर की सफाई का वही पुराना तौर-तरीका कैसे बना हुआ है? यह किसी से छिपा नहीं है कि हर कुछ रोज के बाद देश के किसी न किसी हिस्से से सीवर की सफाई के दौरान लोगों के मरने की खबरें आती रहती हैं। इस तरह की हर घटना के बाद राहत और कार्रवाई का आश्वासन देने में कोई कमी नहीं करने वाली सरकार के सामने सरेआम सीवर में जोखिम के हालात में सफाई का काम होता रहता है, लेकिन नेता से लेकर संबंधित महकमे के अधिकारी इसके प्रति अपनी आंखें मूंदे रखते हैं।

एक बड़ी समस्या यह भी है कि ऐसी हर घटना में आमतौर पर जिम्मेदार ठेकेदारों को शायद ही कभी ऐसी सजा हो पाती है जिससे बाकी लोग सबक ले सकें। यही वजह है कि सरकार के स्तर पर सीवर की सफाई का काम ठेकेदारों को सौंपा जाता है और वे बिना किसी संकोच या डर के सफाई मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के भारी जोखिम के बीच जहरीली गैसों से भरे सीवर में उतार देते हैं। कानूनन गलत और अमानवीय होने के बावजूद क्या यह सब इसलिए बिना रोकटोक के चलता रहा है कि इस काम में लगे मजदूर आमतौर पर सामाजिक पायदान के सबसे निचले हिस्से और कमजोर तबके से आते हैं! यह सवाल भी स्वाभाविक है कि अगर हम विज्ञान की शानदार कामयाबियों के साथ उच्च स्तर के मशीनों और यंत्रों का निर्माण और उनके उपयोग से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं तो सीवर की सफाई के लिए अब तक इंसानों को ही जहरीले गैसों से भरे नालों में मरने के लिए क्यों उतरना पड़ता है?

कल्पमेधा

नशे के मामले में हम बहुत ऊंचे हैं। दो नशे खास हैं- हीनता का नशा और उच्चता का नशा, जो बारी-बारी से चढ़ते रहते हैं।
-हरिशंकर परसाई

अंतरिक्ष का सामरिक महत्त्व

के सिद्धार्थ

अंतरिक्ष की राजनीति, इसके आर्थिक फायदे उठा लेने से भी ज्यादा किसी भी देश के अपना बचाव या दूसरे पर हमला करने की क्षमता से भी जुड़ी है। यह तो समय ही बताएगा कि अंतरिक्ष का ज्ञान किस तरह पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले मानव और उसके भविष्य को तय करेगा। अंतरिक्ष की तकनीक, उसकी समस्या, उसका प्रबंधन और उसका उपयोग अब एक अलग उद्योग है। जो देश इसमें आगे होंगे, वे न केवल पैसा कमाएंगे बल्कि एक नए समुदाय का निर्माण करेंगे।

इक्कीसवीं सदी में अंतरिक्ष की नई होड़ न तो अप्रत्याशित है और न ही बिना सोची-समझी। अंतरिक्ष ही पृथ्वी और मानवता का भविष्य भी हो सकता है और भविष्य का युद्ध स्थल भी। इसलिए अंतरिक्ष पर नियंत्रण और प्रभुत्व जमाने के लिए उन सभी देशों में होड़ लगी है जो या तो महाशक्तियां हैं या फिर महाशक्ति बनने की मंशा रखते हैं। अंतरिक्ष का नियंत्रण और इसका उपयोग ही है जिसके कारण आज दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी जैसी संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और संचार नेटवर्क ने ही पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। अंतरिक्ष मानव जाति के कल्याण का रास्ता तो है ही, साथ ही अब यह आर्थिक लाभ का और इससे भी अधिक आक्रमण और रक्षा करने का भी रास्ता बन गया है। अमेरिका ने चांद पर मनुष्य भेज कर पूरे विश्व में अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा लिया था, जिससे वह शीतयुद्ध में सबसे आगे निकलने में सक्षम हो गया। आज अमेरिका इसी क्षमता को आर्थिक रूप से भुना रहा है।

शीतयुद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक-दूसरे को पीछे छोड़ कर अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व जमाने की होड़ में लगे थे। शीतयुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अंतर-महाद्वीपीय मिसाइल भी अंतरिक्ष तकनीक का ही हिस्सा थी। अब इससे भी आगे जाने की बारी है। अपने निकटतम उपग्रह चंद्रमा पर जाकर अपना प्रभुत्व जमाने की यह होड़ अब शुरू हो गई है। भारत के इस होड़ में कूदने के बाद अब यह और तेज होगी।

अंतरिक्ष का विकास अब तक नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रसारण और नौ-संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपग्रह संचार पर केंद्रित रहा है। पर अब कई चीजें बदल रही हैं। प्रौद्योगिकी अपनी ज्ञात सीमा से आगे बढ़ रही है और डिजाइन का उपयोग भी विविध और ज्यादा मानवतावादी हो गया है। भू-राजनीति पृथ्वी की निम्न-कक्षा की उथल-पुथल से आगे मनुष्यों को भेजने के लिए एक नई होड़ पैदा कर रही है। चीन 2035 तक लोगों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि 2024 तक अमेरिकी फिर चंद्रमा पर जाए। इस तरह के साहसी मिशनों के लिए निजी क्षेत्र का दखल बढ़ रहा है। सन 1958 और 2009 के बीच अंतरिक्ष में लगभग सभी खर्च सरकारी एजेंसियों खासतौर से नासा और पेंटागन ने उठाए थे। पिछले एक दशक में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश सालाना औसतन दो अरब डॉलर या कुल खर्च के पंद्रह फीसद तक बढ़ गया है। यह और अधिक बढ़ने के लिए तैयार है। स्पेस-एक्स तो इक्कीस सफल उपग्रह छोड़ चुकी है। अब अंतरिक्ष पृथ्वी का ही एक विस्तार बनने की ओर है। यह केवल सरकारों के लिए नहीं बल्कि कंपनियों और निजी व्यक्तियों के लिए एक नया क्षेत्र बनेगा। लेकिन इसे पूरा करने के लिए दुनिया में अंतरिक्ष के कानूनों की एक व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ेगी और ये ही नियम शांति और युद्ध में भी कारगर भूमिका निभाएंगे।

अंतरिक्ष की राजनीति, इसके आर्थिक फायदे उठा लेने से भी ज्यादा किसी भी देश के अपना बचाव या दूसरे पर हमला करने की क्षमता से भी जुड़ी है। यह तो समय ही बताएगा कि अंतरिक्ष का ज्ञान किस तरह पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले मानव और उसके भविष्य को तय करेगा। अंतरिक्ष की तकनीक, उसकी समस्या, उसका प्रबंधन और उसका उपयोग अब एक अलग उद्योग है। जो देश इसमें आगे होंगे, वे न केवल पैसा कमाएंगे बल्कि एक नए समुदाय का निर्माण करेंगे। यह उन देशों की नई शक्ति का परिचायक भी होगा। सबसे अच्छी बात है कि भारत अब इस सबका हिस्सा है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर अब अंतरिक्ष को एक नए नजरिये से देखने की जरूरत बढ़ जाती है।

अगले पचास साल अंतरिक्ष के लिए काफी अलग और रोमांच भरे होंगे। अंतरिक्ष की नई उपयोगिताओं की खोज, रक्षा क्षेत्र के लिए इसका अधिक से अधिक उपयोग, हमले और निगरानी के मकसद से उपयोगिता बढ़ाने के रूप में उपग्रहों को गिराने की लागत, चीन और भारत जैसे देशों की अंतरिक्ष में बढ़ती महत्त्वाकांक्षाएं, ये सभी मिलकर ऐसे पहलू हैं जिनमें उद्यमियों की एक नई पीढ़ी अंतरिक्ष विकास के नए युग का आगाज करने वाली है।

अंतरिक्ष एक नया युद्ध क्षेत्र होगा। पहला उपग्रह छोड़े जाने के साठ साल बाद अंतरिक्ष अब सैन्य होड़ का नया मैदान बन गया है। यही वजह है कि इस पर विकसित देश कब्जा करना और हावी होना चाहते हैं।

पिछले साल अमेरिका ने अपनी सेना की छठी शाखा की स्थापना करके संकेत दिया था। उसने अपनी 'स्पेसफोर्स' के साथ एक अमेरिकी अंतरिक्ष कमान बनाई है। अंतरिक्ष और साइबर युद्ध के लिए जिम्मेदारियों के साथ चीन ने 2015 में अपनी सेना की पांचवीं शाखा 'स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स' बनाई। इसी संदर्भ में भारत ने रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) की स्थापना की शुरुआत की है। सैन्य उपयोग को लेकर अंतरिक्ष ने शुरू से ही रुचि जगाई है। वास्तव में अधिकांश अंतरिक्ष कार्यक्रम सैन्य उद्देश्यों से ही संचालित थे। बाहरी अंतरिक्ष संधि (आउटर स्पेस ट्रिटी) अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। यह आकाशीय पिंडों पर सैन्य ठिकानों को बनाने पर रोक लगाती है। पर यह अंतरिक्ष में पारंपरिक सैन्य गतिविधियों, अंतरिक्ष-उन्मुख सैन्य बलों या अंतरिक्ष में पारंपरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाती। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी बनाने का फैसला भारत के किफायती अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों के नियंत्रण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआइए) और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान कार्यालय (एनटीआरओ) जैसी एजेंसियों के माध्यम से काम किया जाएगा। अधिकांश देशों में अंतरिक्ष के नागरिक कार्य उनके अनिवार्य रूप से सैन्य कार्यक्रमों का एक हिस्सा थे। भारत का एक अलग रुख था जिसने जोर देकर कहा कि उसका कार्यक्रम विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है।

रक्षा के अलावा अंतरिक्ष खुद को एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। अंतरिक्ष कमाई के नए स्रोत के रूप में विकसित हो रहा है और निश्चित रूप से यह सभी के लिए समृद्ध और बेहतर संचार नेटवर्क के लिए पर्यटन को शामिल करेगा। लंबे समय में इसमें खनिज दोहन और यहां तक कि बड़े पैमाने पर परिवहन शामिल हो सकता है। ये कुछ नए व्यावसायिक मॉडल हैं जो या तो विकसित हो रहे हैं या होने के करीब हैं। अंतरिक्ष में ये नए व्यवसाय अब बहुत भिन्न हैं। इनमें निचली कक्षाओं में संचार उपग्रहों के समूहों को प्रक्षेपित करने और रखरखाव का बड़ा कारोबार और अमीरों के लिए पर्यटन प्रमुख हैं। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक अंतरिक्ष उद्योग का सालाना राजस्व दोगुना होकर आठ सौ अरब डॉलर हो सकता है। कुछ लोग मंगल पर बसने की इच्छा रखते हैं। अमेजन के संस्थापक आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने की शताब्दी से पहले लाखों लोगों को अंतरिक्ष स्टेशनों पर रहते देखना चाहते हैं।

अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधि के लिए कोई प्रोटोकॉल या नियम नहीं है। अमेरिका, चीन और भारत तेजी से अपनी विनाशकारी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। लेजरों के साथ सैन्य उपग्रहों को अंधा कर रहे हैं, पृथ्वी पर उनके संकेतों को जाम कर रहे हैं या यहां तक कि उड़ा देने की ताकत भी हासिल कर ली है। नतीजतन, ब्रह्मांड में मलबा बिखरता जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। अंतरिक्ष और चंद्रमा मिल कर पृथ्वी का विस्तार बन सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना पृथ्वी की उन समस्याओं को कई गुना बढ़ा सकता है जिनमें सुधार करने की कोशिश देश स्वेच्छा से या अनिच्छा से कर रहे हैं।

कुदरत में हिस्सेदारी

वर्षा सिंह

दुनिया मेरे आगे

मेरी खिड़की के उस पार तोतों का एक दल अभी-अभी उड़ कर गया है। घर के पिछले हिस्से में बोए गए मक्के अब तोड़ने लायक हो गए हैं। परिंदे उस पर अपना अधिकार जमाने आ पहुंचे हैं। वे सारी मक्कियां चख-चख के न छोड़ दें, इसलिए मेरी पड़ोसन अपने छोटे-से खेत में डंडी पर शर्ट लगा कर और मटका टांग कर उन्हें डराने की भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन परिंदे भी कहां हार मानने वाले हैं! वे तय कर चुके हैं कि अपना हिस्सा लेकर रहेंगे।

लगातार बारिश से तर जमीन पर पड़ती चटक धूप तितलियों को भी भा रही है। वे जितना ऊंचा उड़ सकती हैं, उड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बारिश में धुले-धुले पेड़-पौधे, आंवले के फल आने की आहट, कद्दू के पीले फूल, अपने पूरे कद में बढ़ गई भिंडी, इस सीजन को अलविदा कहता चीकू, खूब सारी मिठास बांटने के बाद सुस्ताते आम के पेड़, थोड़े विराम के बाद अगले मौसम की तैयारी करेंगे, बारिश-धूप हवा-मिट्टी-पानी, कीट-पतंगों के कुदरती संयोजन पर टिका इनका जीवन, मेरे कमरे की खिड़की के पार, धरती के इस टुकड़े पर ऊर्जा से भरपूर एक सुंदर चित्र रचता है।

बारिश के पानी में पूरी तरह भीगे अगस्त के इस तीसरे हफ्ते में जब हम कुदरत को उसका शुक्रिया अदा कर सकते थे, उसी समय में हिमालय पर उफनी नदियां विकास के सारे नारे तोड़ रही हैं। घर टूट रहे हैं, दुकानें और सड़कें टूट रही हैं। पहाड़ पत्थर बरसा रहे हैं। नदियां अपने तेज बहाव में सब कुछ ले जाने पर आमादा हैं। बच्चे-बूढ़े सब। नदियां हमसे गुस्साई हुई हैं, नाराज हैं। हमने उनका आंगन छीन लिया है। बारिश में जब खूब पानी आता था तो वे दोनों बाहें पसार कर अपने आंगन तक पसर जाती थीं। गरमी में झुलसते जिस्म के साथ बेबस होती वे भी बारिशों का इंतजार करती होंगी, जब वे लौटेंगी अपने पुराने स्वरूप में।

बारहमासा नदियों के घर में ज्यादातर समय अब सिर्फ पत्थर-बजरी दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि यहां कभी एक नदी हुआ करती थी, जो अब बरसाती नदियां होकर रह गई हैं, जिनके दायरे में हमारी बस्तियां उग आई हैं। लगता है कि नदियां भी यह फैसला कर चुकी हैं कि वे अपना हक लेकर रहेंगी। वे हमारे घरों में जबरन घुसेंगी। जैसे हम उनके घरों में घुस गए हैं। वे हमारे सामान बहा ले जाएंगी। हमारी सड़कें तोड़ ले जाएंगी। उत्तरकाशी हो या शिमला, हम अपने आंसुओं के साथ बेबस खड़े हैं। हमने नदियों के आंसू कब देखे हैं! नदियों के पास उनके खूब पसरने-खेलने भर जगह होनी ही चाहिए। हमारी चौड़ी सड़कों की जिद पूरी करने के लिए काटे गए पहाड़ भी गुस्साए हुए हैं। वे टूट-टूट कर गिर रहे हैं जिनकी पहले से कमजोर दीवारों को काट कर हमने और खोखला कर दिया है।

अमरूद के एक पेड़ से एक छोटी चिड़िया अभी-अभी उड़ कर गई। वह इस समय तबाही का शोक मनाना नहीं चाहती। वह पक रहे अमरूदों का आनंद लेना चाहती है। अपनी छोटी-सी चोंच से कुरेद कर वह उनकी खुशबू हवा में फैला देगी। चिड़िया के ठीक बाद गिलहरी की बारी है। वह भी उसी शाख पर उछल-कूद मचा रही है। क्या पता उसे भी अमरूद अच्छे लगते हों! स्कूल से लौटते उस बच्चे की निगाह भी अमरूदों पर पड़ चुकी है। वह आने-जाने वालों को गुजर जाने का समय देगा और फिर एक ऊंची छलांग लगाएगा, ताकि अमरूद उसकी पकड़ में आ जाएं। पेड़ों में हरकत होते देख कर दूसरी खिड़की से उस बूढ़े की आवाज आएगी, जिसने इन अमरूदों को पकने के लिए दो दिन का समय और दिया है। वह फिर उसे बड़े करीने से तोड़ेगा। लेकिन बच्चा काम अपना बखूबी अंजाम देकर जा चुका है। बूढ़ा अब दूसरे अमरूदों पर गौर करेगा। चिड़िया भी नया निशाना साधेगी।

आसमान में बादलों के आवागमन से होती धूप-छांव संदेश दे रही है कि बारिश फिर शुरू हो सकती है। घर के सारे काम पूरे कर थकी स्त्री का मन ऊबता है। वह अभी बाहर सूख रहे कपड़े उतारना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि ये चमत्कारी खिड़की, जिससे जीवन इतना समृद्ध और हरा-भरा दिखता है, सबके घरों में, सबके हिस्से में होनी चाहिए। खिड़की के उस पार आम-आंवले, लीची-अमरूद के पेड़ होने ही चाहिए। फूलों के साथ कुछ सब्जियां भी होनी चाहिए, ताकि किसी समय यों ही कुछ ऐसे दृश्य दिख जाएं। तोतों का झुंड हमारे इर्द-गिर्द होना ही चाहिए। पकी हुई मक्कियों और अमरूदों में उनका हिस्सा तय होगा। ये सब होगा तभी तो हम चिड़िया के जूठे किए हुए मीठे अमरूद को चख सकेंगे। तितलियां नहीं होंगे तो जीवन में रंग कौन भरेगा? चकाचौंध भरे बाजारों, मॉल, होटलों से जब हम घर लौटें तो घर पर चिड़िया की मीठी धुन, गिलहरी की उछल-कूद मिलनी चाहिए!

बाढ़ की विभीषिका

नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो विश्व के अनेक भागों में करोड़ों रुपयों की संपत्ति को निगल जाती है। गांव के गांव पलक झपकते ही जल समाधि ले लेते हैं। हरे-भरे खेत, लहलहाती फसलें, बाग-बगीचे, घर आदि देखते-देखते नदियों की तेज धारा के साथ बह जाते हैं। अनगिनत पेड़-पौधे और दुर्लभ वनस्पतियां पानी के बहाव के साथ विलीन हो जाती हैं। सैकड़ों लोग और लाखों पशु बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं।

भारत विश्व के उन देशों में से है जहां प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में बाढ़ आती रहती है। केंद्र और राज्य सरकारें बाढ़ की विभीषिका को कम से कम करने के लिए योजना काल से ही प्रयत्नशील हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में अलग से धन की व्यवस्था की जाती है। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में जगह-जगह 'चेकडैम' बना कर और तटबंध व जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में ऐसा कर लिया गया है वहां बाढ़ की विभीषिका काफी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा भूमि की अत्यधिक कटाई कर खेती योग्य भूमि बनाने या वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण लगा कर हम बाढ़ से राहत पा सकते हैं।

नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर भूमि कटाव को कम किया जना चाहिए। उनके किनारे बसे कस्बों एवं शहरों में जो विस्तार या विकास हो रहा है उसमें पानी की उचित निकासी की ओर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। गंदे नालों की सफाई समय से कराई जाए। शहर के निचले इलाकों में मकान न बना कर वहां पार्क एवं खेलकूद के मैदान आदि बनाए जाएं। बाढ़ के हालात पैदा होने से रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक उपाय किए जाना बहुत जरूरी है। इन उपायों से बाढ़ और जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न न होने देने में सहायता मिलेगी।

● *संजय कुमार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

अपराध की डगर

संस्कार हीन शिक्षा और रातोंरात लखपति बनने की अंधी हसरत युवा वर्ग को अपराध के दलदल में धकेल रही है। अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त नाबालिग समाज के समक्ष एक प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे हैं। विलासिता पूर्ण जीवन शैली, नशाखोरी और भौतिक जगत की चकाचौंध नई पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रही है। आसानी से पैसा पाने की अनुचित लालसा अपराधों को बढ़ावा दे रही है। मोबाइल की लत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपना गुलाम बना रही है। इसके मद्देनजर स्कूलों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही परिवार संस्था भी बच्चों को अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

सिनेमा और समाज

सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता रहा है पर अब विडंबना है कि समाज सिनेमा का आईना होता जा रहा है। बात सिर्फ बलात्कार और यौन शोषण की नहीं बल्कि चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी, नशाखोरी, रेव पार्टियां आदि और भी कई आपराधिक गतिविधियां अधिकांश मामलों में कहीं न कहीं सिनेमा से प्रभावित हैं। ऐसे में निर्माता, निर्देशक व अभिनेता-अभिनेत्रियों की समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन इस जिम्मेदारी का भार वहन करने की किसी में हिम्मत नही हैं, क्योंकि बाजारवाद के आगे उन्हें ये जिम्मेदारियां खोखली नजर आती हैं।

● *पुखराज सोलंकी, भीनासर, बीकानेर*

जेहादी सोच

भारत सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कश्मीर से धारा 370 व 35-ए को निष्प्रभावी समाप्त कर दिया। आम कश्मीरियों ने इस फैसले का स्वागत किया और तीस साल में पहली बार ईद की नमाज के बाद कोई दंगा नहीं हुआ जबकि 370 हटाने का विरोध कश्मीर के कई नेताओं ने जम कर किया। अब इन नेताओं से भी ज्यादा विरोध पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भारत सरकार का अगला निशाना 'पीओके' यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और बलूचिस्तान हैं।

इसके कारण बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वे आतंकी हमलों की धमकी देने से भी नहीं चूक रहे हैं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में पुलवामा जैसे आतंकी हमले होने की धमकी दी। उसके बाद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उसके राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत युद्ध करता है तो पाकिस्तान के पास जेहाद और मुकाबला करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा।

पाकिस्तानी नेता शायद भूल गए कि दशकों से उनका देश आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है जबकि आमने-सामने के युद्ध में उसने भारत से हर बार मुंह की खाई है। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा आतंकवाद का डट कर मुकाबला किया है और वसुधैव कुटुंबकम व विश्व शांति का संदेश देते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा है।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

मिलावट का जहर

देश में बिकने वाले चर्चित शीतल पेयों की विभिन्न तरह की जांच से साबित हो चुका है कि उनमें पाए जाने वाले लिडेन, डीडीटी, मैथिलियो और क्लोरपाइरिफॉस की वजह से कैंसर, स्नायु, प्रजनन तंत्र, दांत, यकृत व गुर्दे से संबंधित बीमारियां और प्रतिरक्षण तंत्र में खराबी आना आम है। स्वस्थ जीवन का आधार कहे जाने वाले दूध की बात करें तो आज यह मिलावटखोरी का पर्याय बन कर रह गया है। सरसों के तेल में घातक आर्जीमोन, पाम आइल, देशी घी में वनस्पति घी, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ में हरा रंग, हल्दी में रेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक तथा काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना आम बात है। फलों और सब्जियों में रंगत लाने के लिए रासायनिक इंजेक्शन, उन्हें ताजा दिखाने के लिए सीसा व तांबे के घोल का छिड़काव, चना व अरहर में खेसारी दाल, बेसन में मक्का का आटा, दाल और चावल पर बनावटी रंगों से पॉलिश की जाती है। यह मिलावट देशवासियों की जान पर भारी पड़ रही है मगर अफसोस की बात है कि इसके खिलाफ अपेक्षित रफ्तार से प्रभावी कार्रवाई का सर्वथा अभाव है।

● *देवेंद्र जोशी, महेशनगर, उज्जैन*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com